नई सोच, नया आयाम

जोहार छत्तीसगढ़

RNI No. CHHHIN/2009/35020

दैनिक हिन्दी

◆ वर्ष: -14 ◆ अंक: 251 डाक पंजीयन 030/रायगढ़/2015-2017 ◆ मूल्य: 2 ₹ ◆ पृष्ठ : 4

धरमजयगढ़, बुधवार 20 जुलाई 2022

JOHAR CHHATTISGARH epaper for login www.joharchhattisgarh.in

पेज -3 पर

बेमेतरा पुलिस ने अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप एवं चेतना...

आजादी के 75 वर्षों में पहली बार आवश्यक खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया-रश्मि

पेज -4 पर

'केंद्र सरकार ने जीना दूभर कर दिया'- सीएम भूपेश

भूपेश बोले- केंद्र ने दही-पनीर तक में जीएसटी लगाया, हम गौमूत्र से कीटनाशक भी बनाएंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के बहाने केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने दही-पनीर तक पर जीएसटी लगा दिया है। ये चीजें रोज के इस्तेमाल की हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जीना दूभर कर दिया है। डॉ. खूबचंद बघेल की जयंती आयोजन में शामिल होने रायपुर के व्यावसायिक परिसर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। वह गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो या फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो। वह आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। यह केंद्र सरकार है जो इस जुगत में रहती है कि कैसे भी करके आम आदमी की जेब से पैसा निकाले।

डॉ. बघेल की प्रतिमा पर भी किया माल्यार्पण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित डॉ. खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर पहुंचकर डॉ. बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉ. बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नद्रष्टा थे। उन्होंने एक गंभीर चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक, समाज सुधारक, लेखक के साथ ही कलाकार की भूमिका निभाई। वे जीवन भर रचनात्मक और किसान-मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे।

रायपुर में गोबर खरीदी में गड़बड़ी

न लिया जा रहा था ग्रामीणों से गोबर, न बना रहे थे कम्पोस्ट

रायपुर। रायपुर जिले के नए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे का फोकस शासन की फ्लैगशिप गोधन न्याय योजना पर है। मंगलवार को कलेक्टोरेट में हुई बैठक में उन्होंने इस योजना के तहत किए जा रहे काम काज की समीक्षा की। कुछ जगहों पर अफसर कोई मॉनिटरिंग न होने की सूरत में लापरवाही कर रहे थे। ऐसे अफसरों को कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया। दो टूक सभी से कह दिया कि गोधन न्याय योजना में किसी तरह की लापरवाही न करें। गोबर खरीदी में गड़बड़ी और वर्मी कम्पोस्ट बनाने के काम में धीमी गति डॉ भूरे को रास नहीं आई। उन्होंने अभनुपर के एसएडीओ और चांपा के आरएईओ को नोटिस जारी करवा दिया है। ये कारण बताओ नोटिस अफसरों को एक चेतावनी की तरह है, इसके बाद भी लापरवाही मिली तो कलेक्टर ने कार्रवाई करने की बात कही है।

इन बातें पर नाराज हुए कलेक्टर

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि गौठानों में आवक के हिसाब से लगातार गोबर खरीदी करें। चेताते हुए कहा कि गौठानों में गोबर खरीदी नही करने की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रभारी के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कई गौठानों में अपेक्षित मात्रा से कम गोबर खरीदी पर कलेक्टर भड़क गए, गौठानों में बने वर्मी टैंक के खाली रह जाने की भी अधिकारियों से जानकारी ली।

लापरवाही मिलने पर अभनुपर विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एच.सी साहू और तिल्दा-चांपा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अमित लकरा को नोटिस दे दिया।

एक नजर

राज्यपाल से डी. के. व्यास ने सौजन्य मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

रायपुर । राजभवन में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से डी. के. व्यास के नेतृत्व में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के कर्मचारियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर डी. के. व्यास ने राज्यपाल सुश्री उइके को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर युवराज दुबे और विधान तिवारी उपस्थित थे।

फैक्ट्री में काम करते मजदूर की मौत

रायपुर । सिलतरा स्थित वंदना ग्लोबल कंपनी के सेण्डर प्लांट के अंदर कनवेयर बेल्ट में फंस जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। मामले में धरसींवा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी छत्रपाल साहू 24 वर्ष ने थाने में शिकायत किया कि मृतक सूरज साहू 20 वर्ष ग्राम जोरातराई दुर्ग का रहने वाला था। मृतक वंदना ग्लोबल कंपनी सिलतरा के सेण्डर प्लांट में काम करता था। बताया जाता है कि काम करने के दौरान वह कनवेयर बेल्ट में फंस गया और उसकी मौत हो गई।

एक ऐसा गरीबी मुक्त गांव, रहने के लिए घर नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, फिर भी प्रशासन के नजर में गरीबी मुक्त गांव

जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम पंचायत दर्रीडीह का आश्रित ग्राम खलबोरा जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले लोग रहते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस गांव में लाखों नहीं करोड़ों रूपये पानी की तरह बहाया जा रहा है।

जोहार छत्तीसगढ़ विशेष खबर

लेकिन हकीकत में लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी बिरहोर परिवार आज भी मूलभूत सुविधा से कोसों दूर हैं। प्रशासन ने इस गांव को गरीबी मुक्त गांव का दर्जा दिया है जी हां आप चित्र में देख सकते हैं। कि प्रशासन द्वारा कितना अच्छा दीवाल पेंटिंग किया है। लेकिन ठीक इसी के बगल में रहने वाले बिरहोर परिवार के पास रहने के लिए एक मकान नहीं है। कहने को तो बिरहोर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं पर सुविधा के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मजेदार बात है कि प्रशासन इस गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है। पर शहर आने जाने के लिए एक सड़क नहीं है। जब तक गांव को शहर से जोड़ा नहीं जायेगा तब तक गांव का विकास की बात करना बेईमानी होगी। आपको बता दे कि रायगढ़ जिले में पदस्थ होने वाले लगभग सभी कलेक्टर इस गांव का दौरा करते हैं। फिर भी खलबोरा से धरमजयगढ़ आने जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं मिलना लोगों के समझ से परे है कि क्या कलेक्टर को दिखाई नहीं देता कि इस गांव में आने के लिए कितना परेशानी हो रहा है। विकास के नाम पर इस गांव में प्रशासन ने लाखों करोड़ों अब तक खर्च कर चूके हैं। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रपति के दत्तकपुत्रों को रहने के लिए एक अच्छी घर नसीब नहीं हो रहा है। झोपड़ीनूमा मकान के छत पर प्लास्टिक डालकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन विकास की ढोल पीट रहे हैं और समाचार पत्रों में खूब विकास की बात कर रहे हैंए गाय 10-10 लीटर दूध दे रहे हैं लोग बेचने के लिए गांव से शहर धरमजयगढ़ आ रहे हैं। हकीकत में न तो गाय 10-10 लीटर दूध दे रहा है और न लोग दूध बेचने शहर आ रहे हैं।

सड़क की कोई सुविधा नहीं

प्रशासन द्वारा जिनको गाय बांटा गया उनसे बात करने पर बताये कि गाय दूध तो देती है पर 10 लीटर नहीं देती, जितना भी दूध होता है उसे बेच भी नहीं पाते। क्योंकि गांव से शहर आने के लिए सड़क की कोई सुविधा नहीं है। हकीकत में देखा जाये तो प्रशासन की गरीबी मुक्त गांव खलबोरा के इस योजना से गरीब विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर का गरीबी तो दूर नहीं हुआ पर कुछ लोगों की गरीबी पूरी तरह दूर हो गया है।

स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियां शुरू

मुख्य सचिव जैन ने ली अधिकारियों की बैठक

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह एवं कार्यक्रमों के निर्धारण एवं तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के विभागीय सचिव शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए निर्देशित किया कि राजधानी सहित सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड

ग्राउण्ड में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में परेड सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने एवं समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कलेक्टरों को झंडा वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जायें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के घरों में तिरंगा फहरायें।

भीषण हादसा,जिंदा जल गया ड्राइवर, खड़े ट्रेलर को मारी टक्कर

बिलासपुर। बिलासपुर में भीषण सड़क हादसे के बाद तेज रफ्तार ट्रेलर में आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जल गया। दरअसल, ट्रेलर चालक ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दिया, जिसके बाद वही चालक केबिन में फंस गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई और चालक समेत ट्रेलर जलकर राख हो गया। केबिन में चालक का कंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय हेल्पर भी सवार था, जो सड़क से दूर छिटक कर बेहोश हो

गया। हादसा सकरी थाना इलाके में हुआ है। जानकारी के अनुसार मूलतः बिहार के बक्सर जिले के धनसाई थाना क्षेत्र के भीमखेड़ा निवासी शिव कुमार यादव (27 साल) ट्रेलर चालक था। वह बिलासपुर के किसी ट्रांसपोर्टर की ट्रेलर चलाता था। सोमवार की रात वह बलौदाबाजार स्थित सीमेंट फैक्ट्री से ट्रेलर में सीमेंट लेकर औरंगाबाद जाने के लिए निकला था। घटना मंगलवार सुबह 3.30 बजे की है। अभी ट्रेलर सकरी क्षेत्र के बेलमुंडी-सैदा के पास पहुंचा था। उसी समय सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेलर के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

नाराजगी... सिंहदेव के पत्र पर भड़का मनरेगा संघ

हड़ताल को साजिश बताने से नाराजगी, कहा- आपके विचारों से हम आहत हुए हैं

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे के संबंध में लिखे पत्र से मनरेगा कर्मचारी महासंघ भड़क गया है। संगठन ने नौ बिंदुओं का एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उनके हड़ताल के संदर्भ में सिंहदेव के विचारों से वे लोग आहत हुए हैं।

महत्वपूर्ण यह भी है कि इस पत्र में मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा को उनकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद दिया है।

सिंहदेव ने क्या कहा था, जिसपर आहत हुई भावना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे अपने पत्र में टीएस सिंहदेव ने लिखा था। उसमें कहा गया था कि एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल करवाकर मनरेगा के काम को प्रभावित किया गया। इसमें सहायक परियोजना अधिकारियों-संविदा की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई। स्वयं आपके द्वारा उनकी मांगों पर विचार के लिए कमेटी बनाई गई। उसके बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई। हड़ताल की वजह से 1250 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। जब आपके अनुमोदन से सहायक परियोजना अधिकारियों-संविदा के स्थान पर रेग्युलर सहायक परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति हो गई।

सिंहदेव ने वेतन वृद्धि की फाइल अटकाने का भी आरोप लगाया था

टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने इसी पत्र में कहा था, मनरेगा का काम करने वाले रोजगार सहायकों की मेहनत को देखते हुए उनकी वेतनवृद्धि का प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से भेजा गया था।

जांजगीर में बढ़ रहा डायरिया का खतरा, 7 नए मरीज मिले, 45 हुई

जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में मौसम के बदलने के साथ ही डायरिया का खतरा बढ़ गया है। यहां 7 नए मरीज मिले हैं। जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 45 तक पहुंच गई है। मरीजों के बढ़ती संख्या के मद्देनजर हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे करना शुरू कर दिया है। मामला बलौदा नगर पंचायत का है। दरअसल, हफ्तेभर पहले बलौदा में ये समस्या शुरू हुई थी। शुरुआती दिनों में कुछ ही मरीजों को उल्टी दस्त की दिक्कत थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराने पर पता चला कि इन्हें

डायरिया की समस्या है। जिसके बाद धीरे-धीरे और मरीज बढ़ने लगे थे। अब मंगलवार को की गई जांच में 7 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया डायरिया बलौदा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में फैल चुका है। सबसे ज्यादा मरीज 3, 7 और 10 में मिले हैं। कहा जा रहा है कि यहां पीने के पानी गंदा है। पानी सप्लाई के लिए लगाई गई पाइप में कई जगह लीकेज मिले हैं।

जनता के सवालों पर बहस कब, सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा

रोमानियाई-फ्रांसीसी विचारक एवं नाटककार यूजीन इओनेस्को ने कहा था कि जवाब नहीं, बल्कि सवाल हमारे मन को आलोकित करता है। हालांकि ज्ञानोदय का वादा इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है। सैद्धांतिक रूप से संसद-सत्र के दौरान सांसद सरकार का ध्यान उन लोगों की चिंताओं की ओर दिलाते हैं, जो उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।

लेकिन व्यावहारिक तौर पर सांसदों का ध्यान ज्यादातर दलगत राजनीति पर रहता है और अपने मतदाताओं को परेशान करने वाली चिंताओं पर उनका ध्यान कम रहता है। करदाताओं के करोड़ों रुपये खर्च कर चलने वाली संसदीय प्रक्रिया तेजी से कटु बयानबाजी के अवसर में तब्दील हो गई है। क्या मौजूदा सत्र में सांसद जनता के सवालों पर कुछ समय खर्च करेंगे? जनता को परेशान करने वाले और उनके जीवन एवं जीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक लंबी सूची है। यहां उनमें से कुछ मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है, जिन्हें सांसद शासन की स्थिति की वास्तविक तस्वीर जानने के लिए उठा सकते हैं। मानसून अपने साथ पूर्वानुमानित तस्वीरें लेकर आया है। असम से लेकर गुजरात और उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक, राज्य दर राज्य बाढ़ ने शहरों

सांसदों को एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र की मांग करनी चाहिए। शुरू में वे इस पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि औपचारिक संस्थागत ऋण तक कितने पंजीकृत एमएसएमई की पहुंच है।

और कस्बों में तबाही मचाई है। उल्लेखनीय है कि इनमें से कई शहर स्मार्ट शहरों की सूची में है। पुणे 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं झेल सका। गौरतलब है कि अक्सर शासन की विफलताओं को जलवायु परिवर्तन के व्यापक बहाने के तहत दफन कर दिया जाता है और %अभूतपूर्व% कहकर उसकी भीषणता बताई जाती है। स्मार्ट सिटी की कहानी अपने आप में व्यापक अध्ययन का विषय है। फिलहाल सांसद पूछ सकते हैं कि इस पर कितनी राशि खर्च की गई है और क्या इस कार्यक्रम में आपदा से निपटने के लिए कोई खाका या आवंटन है।

समय आ गया है कि सांसद सरकार को शहरों के अध्ययन का सुझाव दें, ताकि कस्बों, शहरों और राज्यों में पानी की कमी और अधिकता की संवेदनशीलता का मानचित्रण किया जा सके! महामारी ने जीवन, जीविका और बच्चों की शिक्षा को काफी नुकसान पहुंचाया है। 15 लाख से ज्यादा स्कूलों के 24.7 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए, क्योंकि स्कूल 18 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहे। एएसईआर (असर) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, छह से 14 वर्ष के 4.6 फीसदी बच्चे स्कूलों से बाहर पाए गए।

यह सच है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन बच्चों के स्कूल छोड़ने के निहितार्थ राष्ट्रीय हैं। आदर्श रूप में यूडीआईएसई (भारत में स्कूलों के बारे में एक डाटा बेस) के पास इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन आज के डिजिटल शासन के युग में इसकी नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2020ङ्क21 की ही है। सांसदों को घोषित कार्यक्रम के आंकड़े और आकलन के बारे में सवाल पूछना चाहिए। कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं? शिक्षकों के खाली पदों का स्तर क्या है?

ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट एवं उपकरण तक पहुंच के बारे में क्या विचार है? सुधार के किसी भी मूल्यांकन के लिए आधार की जरूरत होती है। इन पंक्तियों के लेखक ने पहले भी इस कॉलम में बेरोजगारी और खाली पदों के विरोधाभास को उजागर किया था। मोदी सरकार ने हाल ही में सरकारी विभागों में 18 महीने में दस लाख पदों को भरने की घोषणा की है। यह स्वागत योग्य विचार है, लेकिन राज्यों में खाली पदों के बारे में क्या योजना है?

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभागों में बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं। केंद्र सरकार में खाली पदों की संख्या (8.5 लाख से ज्यादा) ज्ञात है, लेकिन राज्यों में खाली पदों की जानकारी नहीं है। सांसदों को राज्य स्तर पर खाली पदों की जानकारी मांगनी चाहिए और उन्हें भरने के लिए दबाव बनाना चाहिए। सांसद राज्य सरकारों को रियायत क्यों दे रहे हैं? एक के बाद एक सामने आने वाली घटनाओं ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की भ्रामक तस्वीरों को और बढ़ा दिया है।

भारत ने हमेशा रोजगार की एक सुसंगत तस्वीर पेश करने के लिए संघर्ष किया है, जबकि इसने 1950 के दशक में आंकड़ा संग्रह करने और उसके विश्लेषण का बीड़ा उठाया था। समय-समय पर किए जाने वाले श्रमबल सर्वेक्षण उत्तर से ज्यादा प्रश्न सामने रखते हैं। सरकारी खर्च से मानव-श्रम घंटों, निजी उद्यमों द्वारा भर्ती/छंटनी, ईपीएफओ नामांकन, ई-श्रम प्लेटफार्म पर पंजीकरण और मनरेगा के रिकॉर्ड पेरोल भुगतान पर आंकड़े हैं, पर सुगम संयोजन नहीं है।

निश्चित रूप से इन्हें फिल्टर करके एक पूर्ण नहीं, तो आंशिक तस्वीर प्राप्त की जा सकती है। रोजगार पर एक विश्वसनीय त्रैमासिक रिपोर्ट के लिए सांसदों को संसद और स्थायी समितियों में अभियान चलाना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं-जो न सिर्फ रोजगार पैदा करते हैं, बल्कि उत्पादन एवं निर्यात में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

शंकर अय्यर

संपादकीय

श्रीलंका अब किधर?

नई सरकार के सामने सबसे पहली चुनौती देश में परस्पर विरोधी नजरिए की वकालत कर रही ताकतों के बीच न्यूनतम सहमति बनाने की होगी। ऐसा वो नहीं कर पाई, तो श्रीलंका भंवर में फंसा रहेगा।

श्रीलंका में जन विद्रोह का नजारा दिखा। तीन महीनों से भी ज्यादा समय से आंदोलनकारी राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन वे ना तो गहराते आर्थिक संकट से लोगों को राहत दिलावा पाए और ना ही पद छोड़ने को राजी हुए, तो आंदोलनकारियों ने क्रांतिकारी तरीका अपनाया। बहरहाल, अब जबकि देश की सत्ता एक नई सर्वदलीय सरकार संभालने जा रही है, तो सबसे अहम सवाल यही है कि देश आगे किस रास्ते पर जाएगा? स्पष्टत: श्रीलंका में आंदोलनकारियों के बीच भी इस सवाल पर गहरे मतभेद हैं। ये बात उनके बयानों से जाहिर हुई है। इस दौरान परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। साफ है कि इससमय देश में मौजूद परस्पर विरोधी दृष्टिकोण मैजूद हैं। इसलिए अगली सरकार के लिए आर्थिक कार्यक्रम तय करना आसान नहीं होगा। एक राय है कि देश में तुरंत राजनीतिक स्थिरता बहाल कर सख्त राजकोषीय उपाय लागू किए जाने चाहिए। नई सरकार को तुरंत आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो सके। यह समाज के अपेक्षाकृत सुविधा-संपन्न तबकों की राय है। जबकि आंदोलनकारियों के एक अन्य समूह ने खुला पत्र जारी कर चेतावनी दी है कि नई सरकार आईएमएफ की शर्तों को मान कर जनता की मुश्किलें ना बढ़ाए।

आर्थिक संकट में उलझता पाकिस्तान, आईएमएफ और चीन मदद के लिए तैयार

वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को छह अरब डॉलर की मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तैयार हो गया है। यह अहम इसलिए है, क्योंकि चीन ने कई अरब डॉलर के अपने बकाये के मद्देनजर पाकिस्तान को और मदद देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की बदहाली की ओर ध्यान तब गया था, जब वहां के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने पाकिस्तानियों को रोजाना एक-दो कप कम चाय पीने की सलाह दी! वर्ष 2021-22 में पाकिस्तानी 8,388 करोड़ रुपये की चाय पी गए थे।

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए 15 करोड़ रुपये तक सालाना कमाने वाली कंपनियों पर एक फीसदी, 20 करोड़ रुपये तक कमाने वाली पर दो फीसदी, 25 करोड़ रुपये तक कमाने वाली पर तीन फीसदी तथा 30 करोड़ रुपये तक कमाने वाली कंपनियों पर चार फीसदी कर लगाने का फैसला किया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और संसाधन जुटाने की उसकी नाकामी के कारण उसकी रेटिंग को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। मौजूदा आर्थिक संकट से उसे आईएमएफ ही बचा सकता है, जिसकी कठोर शर्तों को स्वीकार करना पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान को आईएमएफ से मदद हासिल करने में अमेरिका ने परोक्ष रूप से मदद की है। चीन के और मदद देने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान की स्थिति

बताया जाता है कि भारत ने इस आधार पर पाकिस्तान को प्रवेश देने से इनकार किया कि उसकी मौजूदगी अप्रासंगिक होगी, क्योंकि वह खासतौर से आर्थिक सहयोग की दिशा में कुछ नहीं कर सकता।

श्रीलंका जैसी हो सकती थी। कर्ज में डूबे श्रीलंका की बदहाली आज दुनिया के सामने है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं।

यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी नेड प्राइस ने पाकिस्तान को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बताया, जिससे भारत हैरत में पड़ गया। वास्तविकता यह भी है कि भारत-अमेरिका रिश्ता आज नए मुकाम पर है और दोनों देश ड्रैगन को नियंत्रित करना चाहते हैं, जिसने अपनी डेबिट डिप्लोमेसी (कर्ज कूटनीति) के जरिये अनेक एशियाई देशों को फांस रखा है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय ऋण देने वाली एजेंसियों पर ही निर्भर रहा है। उसके पांच दशक का इतिहास देखें, तो उसने लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और बजटीय जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 1972 में 8.4 करोड़ डॉलर, 1973 में 7.5 करोड़ डॉलर और 1974 में एक बार फिर 7.5 करोड़ डॉलर के कर्ज लिए थे। 1977 में आपात आधार पर उसने आठ करोड़ डॉलर और 1980 में 3.49 करोड़ डॉलर के कर्ज लिए। उस देश की वित्तीय हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, जिसके वित्त मंत्री अपने लोगों को चाय कम पीने की सलाह दे रहे हैं। उनकी सलाह पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, तो अब चाय भी छोड़ दें...कल कहेंगे सांस भी न लो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी! अनेक लोगों ने इसे अपने बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। पाकिस्तान के संघीय बजट के दस्तावेज दिखाते हैं कि उसने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1,300 करोड़ रुपये (छह करोड़ डॉलर) मूल्य की अधिक चाय आयात की।

पाकिस्तान को पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में हुई ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक में उस समय तगड़ा झटका लगा, जब भारत की आपत्ति के कारण चीन ने उसे वैश्विक विकास संबंधी एक बैठक में हिस्सा नहीं लेने दिया। बताया जाता है कि भारत ने इस आधार पर पाकिस्तान को प्रवेश देने से इनकार किया कि उसकी मौजूदगी अप्रासंगिक होगी, क्योंकि वह खासतौर से आर्थिक सहयोग की दिशा में कुछ नहीं कर सकता।

केएस तोमर

मिला जुला

आदिवासी नारी शक्ति को समर्पित एक दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ संपन्न

जोहार छत्तीसगढ़-जगदलपुर।

आदिवासी नारी शक्ति को समर्पित एक दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ संपन्न आदिवासी युवा छात्र संगठन महिला प्रभाग जिला बस्तर के द्वारा किया गया। आदिवासी नारियों पर हो रहे शोषण, अत्याचार पर जन जागरूकता लेने के लिए इस आयोजन को किया गया। जिसमें मौजूद अतिथियों ने पुरखों का सेवा अर्जी करते हुए कार्यक्रम को शुरू किया गया जिस पर आए हुए अतिथियों का पारंपारिक महुआ फूल से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जिला कोषाध्यक्ष ने मंच संचालन करते हुए आदिवासी युवा छात्र संगठन महिला प्रभाग के संबध में बताया। इस दौरान मातृ शक्ति सब इंस्पेक्टर तिरुमाय भुनेश्वरी नरेटी ने महिलाओं को एसटी.एससी एक्ट, पांचवी अनुसूची क्षेत्र और महिलाओं के अधिकारों, घरेलू हिंसा, महिलाओं का शोषण, मोबाइल अपराध,आदिवासी अंचलों में बाहरी लोगों का प्रवेश और उनके द्वारा आदिवासियों का शोषण किस तरह से किया जा रहा की जानकारी दी गई इस की जानकारी देते हुए पुलिस के द्वारा जारी एप की जानकारी दिया

गया।

तिरुमाय डॉ. बबीता कवासी

हॉस्पिटल्स में अंदरूनी क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं के केश अधिक आते है जिनको बाहरी लोगों के द्वारा बहला.फु.सलाकर उनके साथ महीनों तक शोषण किया जाता है गलत फ ायदा उठाया जाता है जिसकी वजह से वह महिलाएं में मानसिक विकास इतना कमजोर हो जाता है कि उनका भविष्य डगमगा जाता है वह मानसिक रोग से पीड़ित हो जाती हैं जिनकी लिव लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और आदिवासी महिलाओं को कम उम्र में शादी नहीं करनी की सलाह दी गई। जिसमें उनकी प्रेगनेंसी में एनीमिया की शिकायत पाई जाती है ।

तिरुमाय डॉ. कल्पना नायक

महिलाओं में जागरूकता की कमी के साथ.साथ आत्मविश्वास की कमी भी है कोटा और रिजर्वेशन से उनके सिलेक्शन होने की बात उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट और अपने लक्ष्य से भटकने का कारण है महिलाओं को समिंदा होने वाली बात नहीं बल्कि गर्व करने वाली बात है के हम आदिवासी है और महिलाओं को मेरी यह सलाह है कि शिक्षित बनो,जागरूक रहें,संगठित रहें।

तिरुमाय डॉक्टर दीपिका ध्रुव

बस्तर और सरगुजा जनजाति बाहुल्य संभाग है यह के लोग शिक्षा से पिछड़ा हुए है खुद में आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है युवावस्था में जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार और एक समाज शिक्षित होता है इसलिए नॉलेज गेन करें सोशल साइड का सदुपयोग करें, संघर्ष करें, शासकीय सुविधाओं की जानकारी रखने की आवश्यकता है परिवर्तन ही जीवन का आधार है।

तिरुमाय मालिनी सुब्रमण्यम

महिलाए अपनी स्वतंत्र खोएंगे तो दूसरे पर निर्भर होंगे। मै आदिवासियों के जीवन शैली से प्रभावित हूं आदिवासियों में भ्रूण हत्या नहीं होतीए आदिवासियों में लड़का लड़कियों में भेद भाव नहीं किया जाता। बस्तर की आदिवासी महिलाओ को हल चलाते देखा है वो किसी पे निर्भर नहीं है वे स्वतंत्र है। आदिवासी के सादगी का फायदा बाहरी उठाते है लड़कियों के जन्म से ही निर्णय कोई और ही लेता है जब अंत ने वो आत्महत्या कर लेती है तो भी उसे ही दोसी ठहराया जाता है ये मानव अधिकार का उलंघन है। जब लड़का या लड़की जन्म लेती है तब से वह मानव अधिकार से जुड़ जाती है और उनका ही कर्तव्य है मानव अधिकार का संरक्षण करे।

तिरुमाय योगिया पाथरे

बस्तर में जमीन से संबंधित समस्या अधिक है आदिवासी से गैर आदिवासी विवाह के झासे में ले कर के उनका फायदा उठाता है आदिवासी जमीन का क्रय विक्रय किया जा था है।

इसलिए महिलाएं को सतर्क रहने की आवश्यकता है और पलायन जैसी समस्या भी अधिक है पलायन के दवरान महिलाओं के शोषण किया जाता है। अन्य राज्य में गए महिलाओं को लाने में परेशानियां आती है। इस कार्यक्रम के अतिथि रहे नायब तहसीलदार तिरुमाय योगिता पाथरे, सिटी कोतवाली सब इंस्पेक्टर तिरुमाय गुनेश्वारी नरेटी, स्वतंत्र पत्रकार मानव अधिकार तिरूमय मालिनी सुब्रमण्यम, डीमरापाल हॉस्पिटल डॉक्टर तिरुमाय दीपिका ध्रुव, तिरुमाय डॉ कल्पना नायक असिस्टेंट प्रोफेसर पैथिक डिपार्टमेंट, तिरुमाय डॉ. बबीता कवासी जेआर शिशु रोग विभाग, गोंडवाना समाज महिला अध्यक्ष तिरुमाय शीतला कोर्राम, आदिवासी युवा छात्र संगठन महिला प्रभाग के पदाधिकारी एवं समस्त ब्लॉक के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारी.कर्मचारियों ने लगवाया कोविड का बूस्टर डोज

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

कलेक्टर रितेश अग्रवाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कलेक्टोरेट कार्यालय जशपुर में कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने अपना जागरूकता का परिचय देते हुए बूस्टर डोज को प्राथमिकता के साथ लगवाया। जिसमें जनपद सीईओ जशपुर प्रेमसिंह मरकाम ने बूस्टर लगवाते हुए कहा कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीका अनिवार्य रूप से लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर के माध्यम से जिला

कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगया गया। जिले में कोरोना से बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को आज से नि:शुल्क प्रिकॉशन, बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इस आयु वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगाए 6 माह या 26 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं। उन्हें कोविड टीकाकरण केन्द्रों पर पर प्रिकॉशन, बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह विशेष टीकाकरण अभियान 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक 75 दिनों तक चलेगा। इसके लिए सभी पात्र व्यक्ति 14 जुलाई से कोविन एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं। पहले और दूसरे डोज के रूप में जो टीका लगाया गया है। प्रिकॉशन, बूस्टर डोज के रूप में भी वही टीका लगाया जाएगा। इस हेतु जिले में विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार कर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

नकवी बनाए गए बंगाल के राज्यपाल?

बीजेपी सांसद ने बधाई देकर डिलीट किया ट्वीट

नई दिल्ली। मुख्तार अब्बास नकवी को क्या पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया है? किसी आधिकारिक ऐलान से पहले बीजेपी सांसद ने इसको लेकर ट्वीट किया. उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने पर पहले तो बधाई दे डाली. फिर कुछ ही देर में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। बता दें कि बंगाल के मौजूदा राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ND ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है.

ऐसे में उनकी पोस्ट खाली होने के बाद किसी को उनकी जगह लेनी है. ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सबसे आगे है. इससे पहले राष्ट्रपति की रेस में भी नकवी का नाम था. लेकिन NDA ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था. बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने लिखा था, 'केंद्र सरकार द्वारा मुख्तार अब्बास नकवी को बंगाल का नया राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई.' कुछ ही वक्त बाद हंसराज हंस ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया।

राष्ट्रपति चुनाव

भाजपा के सनी देओल सहित 8 सांसदों ने नहीं डाल पाया वोट

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और फिल्म अभिनेता सनी देओल और केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया. बता दें कि सनी देओल इलाज के लिए विदेश में हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री धोत्रे आईसीयू में भर्ती हैं. भाजपा और शिवसेना के दो-दो सांसद और बहुजन समाज पार्टी (बसपा), कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक-एक सांसद भी उन लोगों में शामिल थे,

जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान नहीं किया. इसके अलावा जेल में बंद बसपा नेता अतुल सिंह मतदान करने नहीं आ सके.

शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर और हेमंत गोडसे ने भी मतदान नहीं किया. एआईएमआईएम नेता इम्तियाज़ जलील भी उन आठ लोगों में शामिल थे जिन्होंने मत नहीं दिया. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे कई वरिष्ठ नेता पीपीई किट पहनकर मतदान केंद्र पहुंचे. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंचे. राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मतपेटियां राष्ट्रीय राजधानी आनी शुरू हो गयी हैं.

कार्ययोजना बनाकर पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगाएं- कलेक्टर

गौठानों में नियमित गोबर खरीदी और वर्मी उत्पादन सुनिश्चित करें

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने समय-सीमा की बैठक में वैक्सीनेशन मोबिलाइजेशन में पहले की अपेक्षाकृत धीमी गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 की बूस्टर डोज कार्ययोजना बनाकर निर्धारित अवधि में जिले के सभी पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगे यह सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आप सभी ने पहले इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। आप लोगों के पास लोगों को वैक्सीन लगाए जाने और उसमें उसमें शत प्रतिशत लक्ष्य पाने का पूरा अनुभव है। आप उसी अनुभव का प्रयोग करते हुए लोगों को बूस्टर डोज लगवाएं। इसके लिए पूरी कार्ययोजना बना ली जाए। एक दिन निश्चित तारीख तय कर पूरे जिले में एक लाख बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वयस्क आबादी ;18 से 59 वर्षद्ध को मुफ्त प्रीकॉशन डोज विगत 15 जुलाई से 75 दिन यानि 30 सितम्बर तक नि:शुल्क लगाया जाएगा। बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए गांव के सरपंच, पंच, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जो रेडी.टू.ईट से जुड़ी महिलाएं राशन दुकान चलाने वाली महिलाएं खेल युवा मंडली आदि से भी सक्रिय सहयोग लिया जाए। टीका शिविरों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी भेजा जाए। जो जहां कमी हो उसके निराकरण पर प्रगति लाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एसआर बंजारे ने वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जेल में बंदियों और स्टाफ को भी डोज लगायी गई है। स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर क्षीरसागर ने कुछ गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी उत्पादन चिंता जाहिर की। उन्होंने पशुपालकों से गोबर खरीदी और वर्मी उत्पादन नियमित तौर पर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गौठानों में संचालित गतिविधियों और स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद सी-मार्ट में भेजने की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि सुराजी गांव योजना शासन स्तर से लगातार समीक्षा होती रहती है। उन्होंने कहा कि हरेली पर्व 28 जुलाई से जिले के दो स्वावलंबी गौठानों बड़गांव एवं बम्हनी में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारी समय रहते पूरी कर ली जाएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस आलोक ने जिले की गौठानों में 7 जुलाई से अभी तक गोबर खरीदी और वर्मी उत्पादन की जानकारी दी।

उन्होंने जनपद सीईओ से कहा कि प्रति गौठानों में कम से कम 2 क्विंटल गोबर की खरीदी की जाए। ताकि 15 दिन में गोबर खरीदी 30 क्विंटल दिखाई दे। इसी प्रकार वर्मी उत्पादन भी होना चाहिए। उन्होंने नगरीय निकायों के गौठानों में गोबर खरीदी पर प्रगति लाने को कहा। कलेक्टर क्षीरसागर ने महानदी के तट एवं अन्य नदी के तट के किनारे बसे गांव में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। ताकि बॉधों से छोड़े गए पानी के चलते जनहानि और धनहानि को रोका जा सके। उन्होंने महासमुंद के चलते भारी बारिश संभावित अतिवृष्टि नदीए नालों के उफान तथा बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर लोगों की जान की सुरक्षा के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने एवं तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने खाद.बीज वितरण की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बारी-बारी से सभी विभागों के लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्य को समय में पूरा करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर संविदा ओपी कोसरिया, डॉ. नेहा कपूर, एसडीएम भागवत जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। जिले के विकासखंड के एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खंड चिकित्सा अधिकारी आदि वीडियों कांफ्रेंस के जरिए जुड़े।

अपर कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आम लोगों की समस्याएं

अधिकारियों को समय सीमा में आवेदनों को निराकृत करने के दिये निर्देश

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अपर कलेक्टर आईएल ठाकुर ने जनदर्शन के माध्यम से ग्रामीण जनों की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आर्थिक सहायता, वेतन भुगतान, रोजगार प्रदाय, मजदूरी भुगतान, पेंशन भुगतान, मुआवजा, वन अधिकार पट्टा, बंटवारा, भूमि-विवाद नामांतरण सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को जनदर्शन में प्राप्त पेंशन, राशन कार्ड, मजदूरी भुगतान, राजस्व संबंधी प्रकरणों का गंभीरता से लेने एवं समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए।

मुढ़ेना तक सड़क निर्माण की बहुप्रतिक्षित मांग हुई पूरी

सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जताया संसदीय सचिव का आभार

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

ग्राम मुढ़ेना तक सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 17 लाख की मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों में हर्ष है। बहुप्रतिक्षित मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर का आभार जताया है। मंगलवार को सरपंच गोवर्धन बांधे के नेतृत्व में मन्नूलाल सिन्हा, रेखू सिन्हा, नरोत्तम देवदास, गजेंद्र साहू, सुदर्शन बारले, दाउलाल सोनवानी, संतोषी निषाद, गीता निषाद, योगेश सिन्हा, सेवक निषाद, रंजीत ठाकुर, लेखराज सोनवानी, मीना यादव, राधा बाई, संगीता, दौवा निषाद, टीकम निषाद, लोकेश निषाद, विजय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, राजकुमारी, किरण, दिव्या, नीतू, देवनारायण, दुकेश्वरी, महेश्वरी, जोहन कोसले, सुरेश साहू लछवंतीन कोसले आदि संसदीय सचिव निवास पहुंचे। जहां संसदीय सचिव चंद्राकर से मुलाकात कर सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 17 लाख की मंजूरी मिलने पर आभार जताया। सरपंच गोवर्धन बांधे ने कहा कि मुख्य मार्ग से मुढ़ेना तक सड़क की स्थिति काफी खराब है। बरसात के दिनों में तो आवाजाही में काफी परेशानी होती है। सड़क निर्माण को लेकर लंबे समय से शासन-प्रशासन का ध्यानाकर्षित कराते आ रहे थे। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी। ससंदीय सचिव चंद्राकर ने सड़क निर्माण के लिए मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि सड़क निर्माण की मांग को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार का ध्यानाकर्षित कराया था। तब जाकर सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 17 लाख की मंजूरी मिल सकी है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों को आवाजाही में सहुलियत हो सकेगी।

जिला पंचायत सीईओ यादव ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक

जिले में प्रिकॉशन डोज एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति लाने के दिए निर्देश

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र यादव द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय.सीमा की बैठक ली गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी जितेन्द्र उपाध्याय, अपर कलेक्टर आईएल ठाकुर, समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में सीईओ द्वारा जिले में वैक्सीनेशन, पौधरोपण, गौठानों में गोबर खरीदी, जाति प्रमाण-पत्र व आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। सीईओ यादव ने जिले में बूस्टर डोज लगवाने की स्थिति की जानकारी लेते हुए पूरे जिले में टीका करण मे प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए कहा साथ ही सभी शासकीय कार्यालय, कॉलेज, स्कूल, बैंक सहित अन्य पब्लिक स्थानों में कैम्प के माध्यम से टीकाकरण करने की बात कही। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद सीईओए सीएमओ को नियमित रूप से अपने क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी लेने के लिए कहा। साथ ही अपने स्तर पर खण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने की बात कही। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस हेतु व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। सीईओ ने जिले में चल रहे वृक्षारोपण की विभागवार जानकारी लेते हुए सभी विभाग को समय पर लक्ष्यानुसार पौधारोपण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी पात्र व्यक्तियों का शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र अभियान चलाकर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। यादव ने गौठानों में गोबर खरीदी एवं खाद निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी गौठानों में नियमित रूप से गोबर खरीदी करने एवं खाद निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने जिले में सक्रिय गौठानों की संख्या बढाने एवं महिला समूह की आय बढ़ाने हेतु गंभीरता से कार्य करने के लिए कहा। इस हेतु गौठान के नोडल अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को धान के बदले अन्य फसल लेनेए केसीसी योजना का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा। इस दौरान सीईओ ने अधिकारियों से समय सीमा के लंबित प्रकरणों को समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से निराकरण करने करने के निर्देश दिए।

एक नजर

जनचौपाल के दौरान सुनी गई आम नागरिकों की समस्याएं

जनचौपाल में मिले 59 आवेदन

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित आम जनता से साप्ताहिक भेंट मुलाकात कार्यक्रम जनचौपाल के दौरान कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ लीना मण्डावी एवं अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी ने जिले के विभिन्न गांवों से आये आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साप्ताहिक जनचौपाल के दौरान बेमेतरा जिले के विभिन्न गांवों से आये आम नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 59 आवेदन प्रस्तुत किये। प्राप्त आवेदनों में समूह की ऋण माफी,शासकीय भूमि में अतिक्रमण हटवाने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की राशि भुगतान कराये जाने, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजनांतर्गत पंजीयन कराने, भूमि सीमांकन करवाने, सहायता राशि प्रदान करने, नया राशन कार्ड बनाने,नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास दिलाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाये जाने आदि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जिला पंचायत सीईओ एवं अपर कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार इसका निराकरण करने के निर्देश दिए। यदि तकनिकी कारणों से निराकरण नहीं हो पा रहा हो तो इसकी सूचना संबंधित आवेदक को भी दी जाये। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकरी राजस्व बेमेतरा युगल किशोर उर्वशा, बेरला संदीप ठाकुर, नवागढ़ प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव म्हस्के, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी, उप संचालक समाज कल्याण अजय कुमार गेडाम, उप संचालक कृषि एमडी मानकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवाओं को पात्रतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ

पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर परिवार के शिक्षित युवाओं से 25 जुलाई 2022 तक आवेदन आमंत्रित

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा क्षेत्र जशपुर में भ्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के शिक्षित युवाओं को उनकी पात्रतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की घोषणा की गई है। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करते हुए जिले के सभी जनपद पंचायतों को निर्देश जारी कर विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर परिवार के शिक्षित युवाओं से 25 जुलाई 2022 तक आवेदन प्राप्त करने को कहा है। अपर कलेक्टर ने बताया कि जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर से प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर पात्रतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर, उन्हें अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदो में से 20 प्रतिशत पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस संबंध में पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर परिवार के शिक्षित युवा अपने क्षेत्र के जनपद कार्यालय में अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जशपुर में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

कोटेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे भाजपाई

नगरी । सावन के पहले सोमवार के अवसर पर कोटेश्वर महादेव पहुंच कर राष्ट्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा एवं पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह एवं पूर्व विधायक श्रवण मरकाम ने पूजा अर्चना एवं दर्शन किए। इस दौरान भाजपा के जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा, भाजपा महिला मोर्चा के वरिष्ठ प्रतिमा देवांगन, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, भाजपा महिला मोर्चा की वरिष्ठ रामेश्वरी साहू,जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम,महिला मोर्चा के जिला महामंत्री हेमलता यादव, महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुलोचना साहू, मंडल मंत्री चेलेश्वरी साहू,पार्षद विनीता कोठारी, मुरारी यदु सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बेमेतरा पुलिस ने अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप एवं चेतना अभियान के माध्यम से किया जागरूक

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्ष ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकेंगी। यानी अब महिलाओं को थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस विभाग तक पहुंचा सकेंगी। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह एवं अति.पुलिस अधीक्षक बेमेतरा पंकज पटेल जिले के अभिव्यक्ति महिला सुरक्ष ऐप के नोडल अधिकारी व अति.पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के निर्देशन पर बेमेतरा जिले में अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा हैं।

इसी कड़ी में 18 जुलाई 2022 को थाना नांदघाट प्रभारी निरीक्षक संतोषी ग्रेस, थाना चंदनू प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शर्मा, उपनिरीक्षक अंजोर सिंह साहू के द्वारा शिक्षकों के उपस्थिति में चेतना कार्यक्रम के तहत शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदराली के छात्र-छात्राओं को महिलाओं एवं बालिकाओं पर हो रहे लैंगिक शोषण के बचाव एवं कारण से सम्बंधित तथा गुड टच, बेड टच तथा सेल्फ डिफेंस महिलाओं पर हो रहे अपराध एवं मोबाइल से सम्बंधित होने वाले साइबर अपराध एवं उनके रोकथाम एवं यातायात के नियम की भी जानकारी दी गयी तथा अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देकर प्रचार प्रसार किया गया।

चिरायु कार्यक्रम अंतर्गत हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का शिविर में परीक्षण एवं ईलाज

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु, कार्यक्रम के अंतर्गत जिला बेमेतरा के आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में स्वास्थ्य टीम के माध्यम से समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जिला कलेक्टर के जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन में जिले में मई, जून, एवं जुलाई माह में रामकृष्ण केयर हॉस्पीटल, रायपुर के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा चिरायु कैम्प में कुल 300 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा भी दी गई है। इस वर्ष कुल 05 पांच का हृदय रोग का सफल ऑपरेशान से ईलज किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी ने बताया की 19 जंलाई 2022, दिन मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डसरा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिन्हांकित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु रामकृष्ण अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा विकासखण्ड स्तरीय में कैम्प का आयोजन किया गया। खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ शरद कोहाडे ने जानकारी दी कि उक्त शिविर में 0.18 वर्ष के बच्चे जो हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, हड्डी रोग, नाक.कान.गला रोग से ग्रसित है। उन्हें चिरायु कार्यक्रम अंतर्गत ईलाज हेतु चिन्हाकिंत किया गया। शिविर में रामकृष्ण अस्पताल रायपुर से डॉ. प्रशांत ठाकुर हृदय रोग विशेषज्ञ की टीम ने 35 बच्चों का जांच किया। शिविर में कुपोषित बच्चों की भी पहचान की गई। शिविर में 10 हृदय रोग, 01 बधिरता रोग, 1 हड्डी रोग आंख की जांच की गई साथ में परिजनों का भी बीपी,शुगर जांच किया गया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो माता-पिता चाहते हुए भी अपने बच्चों का ईलाज करा पाने में असमर्थ होते है। ऐसे परिवार एवं बच्चों की मदद के लिए चिरायु के तहत 30 से ज्याद बिमारियों का ईजाल नि:शुल्क किया जाता है। ऐसे ही भारती गेंडरे, उम्र 10 वर्ष, ग्राम अतरिया, हृदय रोग से ग्रसित चिरायु दल के द्वारा परीक्षण पश्चात कैम्प के माध्यम से रायपुर रेफर किया गया एवं अनुबंधित अस्पताल में नि:शुल्क सर्जरी हुई। अब भारती गेंडरें पुरी तहत से स्वस्थ्य है। डॉ कमलकांत मेश्राम, जिला नोडल अधिकारी, ने अपील की कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हृदय रोग, ऐसे बच्चे जिन्हे कम दिखाई व सुनाई देते है, कटे.फटे होंठ, पैर मुड़े हुए, उनका ईलाज निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क कर चिरायु टीम के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराये। शिविर के आयोजन में जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे, जिला सलाहकार शोभिका गजपाल, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आडिल, चिरायु के मेडिकल ऑफि सर डॉ ऋषभ शर्मा, डॉ विपिन सोनी, डॉ प्रदीप आश्टकर, डॉ देवेन्द्र, खिलेन्द्र साहू, केशर साहू एवं समस्त चिरायु दल के सदस्य उपस्थित रहें।

पोल की फाल्ट सुधारने बांध के अंदर नांव से गए बिजली कर्मी

रोशनी की व्यवस्था में हर बाधा पार कर रहे लाइन कर्मचारी

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

भारी बारिश के चलते एक ओर जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं बिजली सप्लाई निर्बाध रखने में भी बाधाएं आ रही हैं। लगातार बारिश होने के कारण पोल एवं केबल टूट गए हैं तथा कुछ जगहों पर ट्रांसफार्मर एवं पोल पानी से घिर गए हैं या डूब गए हैं।

जोहार छत्तीसगढ़ विशेष खबर

परन्तु फिर भी विद्युत सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद में विद्युत विभाग के कर्मचारी योद्धा की तरह अपनी जान की परवाह किये बिना जुटे हुए हैं। जरुरत पड़ने पर कभी नाव से तो कभी तैरकर फॉल्ट सुधारकर विद्युत व्यवस्था बहाल करने में लगे हुए हैं विद्युत कर्मी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्री ब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के विभागीय संभाग बेमेतरा के अंर्तगत 11 केण्व्ही नवागढ़ फीडर की लाईन 09 जुलाई 2022 फॉल्ट हो गई थी। जिसे सुधारने बांध के अंदर लाइन कर्मियों की टीम नाव से पहुंची। फॉल्ट के कारण ग्राम मुड़पार, बेमेतरा एवं चारभाठा खार की लाईन बंद हो गई। 11 केव्ही लाईन की पेट्रोलिंग करने पर मुड़पार बांध में एक नग पिन इंसुलेटर पंचर पाया गया। सहायक अभियंता गुलाब राम साहू ने बताया कि 11 केव्ही लाइन बांध से गुजरी है।

उन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण बांध में पानी अधिक है। इसलिए नाव की व्यवस्था कर मौके पर पहुंचकर विद्युत कंपनी की टीम ने बड़ी सूझबूझ से पोल पर चढ़कर लाइन दुरुस्त किया। जिससे मुड़पार बस्ती में बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकी। सहायक अभियंता गुलाब साहू ने बताया कि उक्त कार्य करने हेतु बेमेतरा ग्रामीण, के सहायक लाइनमेन सुगनचंद कोशले, लाइन परिचारक श्रेणी दो अमित गिरी एवं डामेश्वर नेताम की टीम तैयार कर लाइन सुधार हेतु भेजा गया था। उन्होंने बताया कि बारिश का पानी अधिक होने के कारण पोल तक नाव के सहारे जाना पड़ा। मुख्य अभियंता एमण्जामुलकर ने कहा कि लाइन कर्मचारी पॉवर कंपनी के आधार स्तंभ हैं जो जीवन संकट में डालकर सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि विपरित परिस्थितियों में भी लाइन कर्मियों के सूझबूझ से कार्य करने का जस्बा प्रशंसनीय है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी उनके इस कार्य की भूरी.भूरी प्रशंसा की जा रही है।

एक नजर

यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चलानी कार्यवाही

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।

जिला मुख्यालय के मलकानगिरी कुम्हार रास कलेक्ट्रेट मुख्य सड़क मार्ग में उपनिरीक्षक शंकर पाल यातायात प्रभारी सुकमा द्वारा बिना हेलमेट पहनने, तीन सावारी दुपहिया व तीन पहिया वाहनों रुटीन चेकिंग कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं लागातार हो रहे सड़क दुर्घटना के बारे यातायात नियमों को सही ढंग से पालन करने के निर्देश दिया गये और शराब पीकर वाहन न चालाए जिससे आप सड़क दुर्घटना कभी भी हो सकती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कृषि महाविद्यालय ढोलिया बेमेतरा के स्वयंसेवकों एवं बालक-बालिका का छात्रावास में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ढोलिया, बेमेतरा के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस स्वयंसेवकों के द्वारा कृषि महाविद्यालय के बालक-बालिका छात्रावास परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। साथ ही साथ महाविद्यालय परिसर में भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर 50 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने भाग लिया और संकल्प लिया की हम अपने परिसर को हरा-भरा एवं इन पौधों की देख.भाल करेंगेष्। रासेयो प्रभारी डॉ. प्रीति पैंकरा के मार्गदर्शन में यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामांकन आवेदन वांछित अभिलेखों के साथ 10 अक्टूबर 2022 तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास जशपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन का प्रारूप बाल न्यायालय परिषदए भागलपुर रोड, रणजीता स्टेडियम के पीछे, जिला बाल संरक्षण अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में 6 वर्ष से 18 वर्ष के बालक एवं बालिका ही आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी जान की परवाह किये बिना, दूसरे की जान बचाने के लिए वीरता का कार्य किया गया हो। शौर्य कार्य 1 जुलाई 2021 से 30 सितम्बर 2022 के मध्य का होना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन के साथ एफआईआर अथवा पुलिस डायरी, समाचार पत्रों, 6 पासपोर्ट साइज के वर्तमान रंगीन फोटो ग्राफ्स जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, संलग्न करना होगा। साथ ही घटना का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।

खाद की हो रही कालाबाजारी होश में नहीं संबंधित अधिकारी

क्यों नहीं हो रहे सहकारी समितियों को खाद की पूर्ति-किसान नेता अशवन्त तुषार साहू

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

जिले के सभी क्षेत्रों के दुकानों में खाद की कालाबाजारी भारी मात्रा में हो रही छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार की घोषणा कर रही है। इधर के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है यूरिया का शासकीय दर 267 वहीं डीएपी का 1300 लगभग लेकिन किसानों को सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है महासमुंद क्षेत्र के किसान परेशान है हलाकान है इधर व्यापारी खाद को अधिक दामों पर बेच रहे हैं खेती करना है यह किसान की मजबूरी है मजबूर होकर किसान अधिक दामों पर खाद खरीद कर रहे है। जोबा,जलकि,तुमगांव, बेमचा, झालखमरिया,बरौंडा, बम्हनी, पटेवा तथा आसपास के सभी सहकारी समितियों में खाद की बहुत अधिक कमी है। जिसके कारण किसानों को उचित दाम में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है वहीं प्राइवेट कृषि केंद्रों में खाद्य का भरपूर मात्रा में भंडारण हो रहा है जिसके वजह से किसानों को खाद कृषि केंद्रों में जाकर व्यापारियों से खाद लेना पड़ रहा है जिसको मजबूरन अध्यक्ष कीमतों में आप खरीदना पड़ रहा है किसानों का जीवनी के लिए यह एक मुख्य आधार है बता दें कि इधर कृषि विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं इसलिए खाद बेचने वाले व्यापारी बेखौफ होकर खुलेआम हाथ को 400 से 500 से अधिक दामों में बेच रहे किसानों को कोई सुध लेने वाला नहीं है क्षेत्र में खाद में पारियों की दुकानों का घर में जांच की जाए तो भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे हाथ बरामद हो सकता है जनता के प्राप्त जानकारी के अनुसार यूरिया 265 है जिसे 700 में वही डीएपी 1300 है उसे 1600 से 1700 तक बेचा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार ढिंढोरा पिट रही है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाए तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है व्यापारियों के पास भारी मात्रा में कहां से और कैसे अवैध रूप से खाद आ रहा है इसकी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए ताकि इसका पार्दाफाश हो सके।

आर ई एस कॉलोनी स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना

कोण्डागांव। दिनांक 18/07/2022 को आर ई एस कॉलोनी स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर में समिति के अध्यक्ष श्रीमती वेदवती पोयम,उपाध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवांगन,सांस्कृतिक प्रभारी श्रीमती जागेश्वरी सोरी समिति के सदस्य श्रीमती कुमुद शर्मा ,प्रियंका शर्मा, मनीष साहू, श्रीमती पूजा साहू, चंदन सोरी ,श्रीमती रमा पिल्ले,श्रीमती अनुसुइया माली तथा समिति के समस्त सदस्यों एवं आर ई एस कॉलोनी वासियों की उपस्थिति में दोपहर 2ः00 बजे पंडित राधेश्याम दुबे द्वारा मंत्रोच्चारण कर प्रथम सावन सोमवार होने के चलते विशेष पूजा अर्चना एवं हवन किया गया ।कार्यक्रम में मुख्य जजमान के रूप में मनोज साहू एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा साहू, कुमारी प्रियंका शर्मा एवं चंदन सोरी रहे । इस अवसर पर पंडित राधेश्याम दुबे द्वारा भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की महिमा का अमर कथा का सुंदर प्रसंग सुनाया गया। पंडित राधेश्याम दुबे ने इस अवसर पर कहा कि श्रावण के महीने में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आराधना करने से अनेकों संकट दूर हो जाते है।

आजादी के 75 वर्षों में पहली बार आवश्यक खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया-रश्मि चंद्राकर

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी सरकार द्वारा खुदरा में मिलने वाले आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, ज्वार, दूध, दही, पनीर, छाछ इत्यादि खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया है। आजादी के 75 वर्षों में पहली बार आवश्यक खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर जीएसटी, के दायरे में लाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने के हर तर्क मौजूद है लेकिन महंगाई कम करने के लिए एक भी उपाय केंद्र सरकार के पास नहीं है आगे चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के मुद्दे पर जनता के समक्ष जवाब देना ही पड़ेगा। अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जनता से 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा।

महासमुंद कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, रोजमर्रा की खाने.पीने की चीजें महंगी हो गईं। गैस सिलेंडर 1000 पार पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। लेकिन मोदी सरकार कहती है ये अच्छे दिन हैं। मतलब, यह महंगाई जनता की समस्या है, सरकार की नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया। जब मोदी विपक्ष में थे, तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं के गहरे दलदल में धकेल दिया है। जिसमें लोग रोज धंसते जा रहे हैं। उनकी इस बेबसी पर प्रधानमंत्री मौन हैं। खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।

खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लागू होने पर चंद्राकर ने कहा। केंद्र सरकार की ओर से आप पर किए जा रहे हर अत्याचार के खिलाफ मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री चाहे जितने शब्दों को असंसदीय बता कर हमें चुप कराने की कोशिश कर लें, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गईं। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं। जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

खाने-पीने की कई चीजों पर जीएसटी लागू खाने पीने की कई चीजों पर 18 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल हैं। इन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। आज से पहले तक जीएसटी के दायरे से बाहर रहे इन सामानों की खरीद पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा रिकार्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा।

बेमेतरा पुलिस ने गुम 65 वर्षीय बुजुर्ग को दस्तयाब कर किया बरामद

परिजनों को किया सुपुर्द

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

प्रार्थी टीकेन्द्र पाटिल उम्र 32 साल साकिन घटियाकला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके पिता केजू राम पाटिल पिता अल्खु राम पाटिल उम्र 65 वर्ष ग्राम घटिया कला जो 3 दिनों से घर से बिना बताये कहीं चला गया है घर के पूरे परिवार वाले काफी परेशान हैं। जिस पर थाना बेरला पुलिस द्वारा गुम इंसान कायम कर जांच पर लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल के द्वारा थाना बेरला प्रभारी नासिर खान एवं थाना स्टाफ को तत्काल गुम बुजुर्ग की पता तलास करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में जांच के दौरान थाना बेरला स्टाफ के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में गुम इंसान की पतासाजी की जा रही थी। जो ग्रामीणों,परिजनो व बेरला पुलिस के प्रयास से केजू राम पाटिल 65 वर्षीय बुजुर्ग गुम इंसान को 17 जुलाई 2022 को दस्तयाब कर बरामद किया गया है 65 वर्षीय बुजुर्ग को उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया। परिवार के सभी सदस्यों ने बुजुर्ग के मिलने पर राहत की सांस ली और 65 वर्षीय बुजुर्ग के परिजनों ने अपने पास पाकर बहुत खुश हुये और खुशी जाहिर करते हुए बेरला पुलिस का हृदय से अभार व्यक्त किये। उक्त पता तलास में थाना बेरला प्रभारी उप निरीक्षक नासिर खान, प्रधान आरक्षक संदीप साहू एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

महिला की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया रतनपुर थाने का घेराव, थाने में पुलिस बल मौजूद

जोहार छत्तीसगढ़-रतनपुर।

रतनपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। भतीजे ने अपनी ही चाची की सब्बल मारकर हत्या कर दी है।

हत्या के बाद फरार भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार हत्या के विरोध में थाने का हुआ घेराव व पथराव।रतनपुर वार्ड नंबर 12 करैहापारा निवासी सुरेखा पाटले सुबह मोहल्ले के नल में पानी भरने गई थी तभी पास आकर सुरेखा के भतीजे मुकेश पाटले पिता मोहित राम पाटले उम्र 22 निवासी करहैया पारा रतनपुर ने सब्बल मारकर हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। लेकिन पुलिस की तत्परता से आरोपी 6 घंटे के अंदर ही पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। हत्या के विरोध में हुआ थाने का घेराव व पथराव महिला की हत्या के बाद से ही गरमाने लगा था माहौल। वहीं शाम होते होते ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार महिला 2 दिन से रतनपुर थाना आकर अपने भतीजे पर ही अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर रही थी। लेकिन पुलिस ने कार्यवाही की जगह महिला को समझाकर वापस भेज दिया था। और आज महिला की हत्या होने पर ग्रामीणों ने इसी बात पर गुस्सा होकर थाने का घेराव किया और थाने पर पथराव भी किया। आनन फानन में रतनपुर थाना प्रभारी ने सहायता हेतु कोनी,कोटा,सीपत थाने से बल बुलाया तब जाकर अभी स्थिति नियंत्रण में है।

तीन बच्चों के सिर से उठा मां का साया

ढाई साल पहले मृतिका सुरेखा पाटले के पति जगदीश की मौत हो गई थी। वह अपने तीन मासूम बच्चों की सहारा थी। महिला की मौत के बाद अब तीनों बच्चों के सिर से मां का छाया भी छीन गया है। उनके बच्चे 10 साल, 6 साल और ढाई साल के हैं। अब बच्चों के सामने जीवन को आगे बढाने की समस्या शुरू हो गई है महिला के हत्याकांड के मामले में मृतिका के परिजनों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस की नाकामी की वजह से हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनो ने बीती रात थाने में हंगामा किया था। जिसकी वजह से उन पर लाठीचार्ज भी हुई थी। जिससे उनका आक्रोश और भी बढ़ गया है। जिन्होंने मंगलवार को मृतिका के अंतिम संस्कार में शामिल न होकर अपना आक्रोश जताया है। जिनकी अनुपस्थिति में पुलिस बल की मौजूदगी में मृतिका का अंतिम संस्कार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब मृतिका के परिजन पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत करने वाले है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक नारायण बाईन, द्वारा आसमा पब्लिसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित कर मेडरमार कालोनी, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित।
संपादक -**नारायण बाईन,** फोन -फैक्स 07766299001, मो, 9479177711, 7489419194 Email-joharchhattisgarh@gmail.com, joharchhattisgarh@yahoo.co.in